PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

**Rashtriya Sahara, Delhi**
**Sat, 03 Jun 2017, Page 9**
**Width: 18.98 cms, Height: 18.58 cms, a3r, Ref: 39.2017-06-03.82**

## आईआईटी, दिल्ली के रुचि न दिखाने के बाद

# सरकार ने हाथ में लिया उन्नत भारत अभियान

■ विनोद के शुक्ल

नई दिल्ली। एसएनबी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम को अब सीधे अपने हाथों में ले लिया है। चूंकि मंत्रालय द्वारा इसके लिए नियुक्त की गई कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली न तो इसके कार्यों में कोई रुचि दिखा रहा था और न ही इसे करने की सही योग्यता नजर उनमें नजर आ रही है।

मंत्रालय ने 45 उच्च शिक्षण संस्थानों को इम्पैनलमेंट करते हुए उनको फील्ड वर्क के लिए भेज दिया है। जब इनकी रिपोर्ट मंत्रालय के अधिकारियों को मिल जाएगी, उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के लिए आईआईटी दिल्ली को नोडल एजेंसी निर्धारित किया था, जिसके दिशा-निर्देश में कार्य आगे किया जाना था। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों के इम्पैनलमेंट समेत कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा था। इसके मद्देनजर सरकार ने इसे अपने हाथों में लेते हुए कार्य आगे बढ़ाया है। इस अभियान में

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसमें कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल किया**

**फील्ड वर्क पूरा होने पर रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी जाएगी**

देश भर के आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थाओं को भागीदारी करनी थी लेकिन मामला जस का तस रहा। अब सरकार ने उन उच्च शिक्षण संस्थानों को, जो गांवों के लिए उपयुक्त हैं, चयनित किया है। गांवों के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। इसलिए कृषि विश्वविद्यालयों जैसे पूसा संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और हैदराबाद और कर्नाटक के कुछ प्रमुख संस्थानों को चयनित किया है।

यह सभी शिक्षण संस्थान 225 गांवों में फील्ड वर्क कर रहे हैं। दरअसल, आईआईटी दिल्ली ने इस काम में इतनी सुस्ती दिखाई कि अब तक वेबसाइट भी नहीं बन पाई है। सरकार इस काम के लिए निर्धारित फंड को इसी काम के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इस पर निगरानी रख रही है। इस योजना के तहत सरकार गांवों में जैविक कृषि, जल प्रबंधन, अल्टरनेट उर्जा संसाधनों, ग्रामीण उद्योग धंधों और रोजगार का विकास और गांवों मे मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है।